

पेज थी

देहरादून

पत्रकार वाता के दौरान डोली यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी व अन्य।



हमारा दून

पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका

आदेश

संवाददाता

देहरादून/नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए उन्हें दी गई सुविधाओं से सबंधित समस्त शासनादेश रद्द कर दिए। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया किराया बाजार दर पर छह माह के भीतर जमा करने के आदेश पारित किया है। साथ ही सरकार को चार माह के भीतर बिजली, पानी, गनर, टेलीफोन, पेट्रोल सति अन्य खर्चों का चार माह में अंकलन कर वसूलने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूर्व सीएम दिवंगत एनडी तिवारी पर बकाया मामले में कहा है कि यदि सरकार चाहे तो उनकी संपत्ति से किराया वसूल सकती है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ देहरादून की रुरल लिटिंग शान एंड एंटाइलमेंट केंद्र रूलक की जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें पूर्व संवाददाता देहरादून। केटीएम ने दून में शानदार स्टंट शो का आयोजन किया संवाददाता देहरादून। केटीएम, यूरोपीय रेसिंग दिग्गज, ने देहरादून में शानदार केटीएम स्टंट शो का आयोजन किया। इसका आयोजन पेशेवर स्टंट राइडर्स के शानदार स्टंट राइडर्स एवं ट्रिक्स का प्रदर्शन करने के लिये किया गया था। इस स्टंट शो का आयोजन ग्राफिक एवं विष्वविद्यालय, देहरादून में किया गया। पेशेवर स्टंट टीमों ने केटीएम ड्यूक्स पर असाधारण स्टंट शो का प्रदर्शन किया।



मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा को सरकारी पर बकाया मामले में कहा है कि यदि सरकार चाहे तो उनकी संपत्ति से किराया वसूल सकती है।

कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया दो करोड़ 85 लाख छह माह के भीतर बाजार दर पर वसूलने का आदेश पारित किया है। इसमें पूर्व सीएम निशंक पर 40.85 लाख, खंडूरी पर 46.95 लाख, बहुगुणा पर 37.50 लाख,

सरकार चाहे तो दिवंगत एनडी तिवारी की संपत्ति से किराया वसूल सकती है

होने से पहले ही अपने लिए सारी सुविधाएं मंजूर करा ली।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि इन पर कुल मिलाकर 2.85 करोड़ रुपये, स्व. एनडी तिवारी पर 4757758 रुपये, स्व. एनडी तिवारी पर 11298182, रमेश पोखरियाल निशंक पर 4095560, भुवनचंद्र खंडूरी पर 4659776 और विजय बहुगुणा पर 3750638 रुपये किराया बकाया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में ही आवास आवंटन अवैध घोषित किये जाने के बाद अब इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की उम्मीद नहीं है।

माना जा रहा है कि उनके पास किराया जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि किराये के अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिजली, पानी, पेट्रोल सहित अन्य सुविधाओं को असंवेधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया।

53 पेज के आदेश में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर तत्क्षण इन्प्रिण्ट करते हुए कहा है कि यह चिंतनीय विषय है कि उनके द्वारा अपने सेवाकाल पूरा

247 दुकानें न बिकी होने से अब तक 600 करोड़ का घाटा

संवाददाता देहरादून। प्रदेशभर की 247 लाइसेंसी देशी-विदेशी शाराब की दुकान बिक्री न होने के चलते आबकारी विभाग को अब तक इस वित्तीय वर्ष का 600 करोड़ का घाटा हो चुका है। जो आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ सकता है। समय बीतने के साथ लगातार घाटे की रकम बढ़ने से आबकारी विभाग की नीद उड़ी हुई है। ऐसे में अब अपने सालाना राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के दबाव में पूर्व वर्षों की भाँति शाराब बिक्री के लिए अब सरकार एजेंसियों का सहारा लेने की योजना बनाई जा रही है। आबकारी विभाग को सरकारी मंडी समितियों द्वारा शाराब बिक्री करने में अतिरिक्त मैन पॉवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहीं घाटे का राजस्व पूरा करने के साथ इस कार्य में पारदर्शिता भी आएगी।

शीतकालीन सत्र में सदन में उठायेंगे पूर्व कर्मचारियों का मामला

कोई कार्यवाही नहीं की गई है: संघ के महामंत्री विपिन जमलोकी ने कहा कि आपातकालीन सेवा 108 के लगभग 717 कर्मचारियों पर संकटहै और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा गया था और इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इस ओर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे रोष बना हुआ और आज उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है।

उनके समर्थन में पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य व भाजपा नेता राविन्द्र जुग्रान ने समर्थन दिया है और कहा कि अब प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जायेगी और इस मामले को शीतकालीन सत्र में सदन में उठाया जायेगा।

धरना स्थल पर उत्तराखण्ड

सफाई कर्मियों के लिए लागू किया जाए नया न्यूनतम वेतन

संवाददाता देहरादून। नये वार्डों के गठन के उपरांत कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स से किए जाने का यूनियन ने घोर विरोध किया है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन ने नगर आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया है। यूनियन ने यह भी मांग की है कि न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से नगर निगम में नियोजित सफाई मजदूरों को नये शासनादेश के अनुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाए। समस्त सफाई मजदूरों का ईपीएफ की कटौती उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार की जानी सुनिश्चित की जाये। ज्ञापन में कहा गया कि नये वार्डों के गठन के उपरांत कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए सफाई व्यवस्था के लिए 600 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाये।

शनैश्चरी अमावस्या 4 को संवाददाता देहरादून। शनैश्चरी अमावस्या 4 मई को पड़ रही है। यह दिन शनि देव को प्रसन्न के लिए सबसे अच्छा होता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक प्रदीप चौधरी द्वारा एल.के प्रिट्स, 74/9, आशागढ़, देहरादून से मुक्ति व जाखन जोहड़ी रोड, पी.ओ.-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित। संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय: शिवम्, मार्केट, द्वितीय तल दर्शनलाल चौक, देहरादून फैक्स नं- 0135-2650558 (M) 9319700701 pagethreediaily@gmail.com आर.एन.आई.नं 0135-2650558 (M) 9319700701 UTTHIN\2005\15735 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Visit Us at <http://app.page3news.co.in>

Supporting Devices

All Apple Touch Phones & Tablets
All Android Touch Phones & Tablets
All Window & BlackBerry Touch Phones 10+

